उद्योग जगत को संरक्षण देगी सरकार : गोयल

गोयल ने उद्योग को एकतरफा कार्रवाइयों से बचाने का आश्वासन दिया

नयी दिल्ली, 29 अगस्त. भारत के खिलाफ अमेरिका जैसे देशों की एकतरफा व्यापारिक कार्रवाइयों के बीच, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार भारतीय उद्योग जगत को ऐसी कठिनाइयों से बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात पिछले साल से अधिक रहेगा.

भारत बिल्डकॉन 2026 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, गोयल ने भारतीय उद्यमियों से विश्वस्तरीय माल बनाने का आह्वान किया. उन्होंने प्रधानमंत्री के शून्य दोष, शून्य प्रभाव (ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफ़ेक्ट) और दाम-कम, दम ज़्यादा के सिद्धांतों को रेखांकित किया. गोयल ने कहा कि इसका मतलब यह है कि उत्पादों को न केवल किफायती होना चाहिए, बल्कि उनकी गुणवत्ता और स्थायित्व भी उत्कृष्ट होने चाहिए. उन्होंने उद्योग जगत से विकसित देशों के साथ हुए हाल के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाने का आग्रह किया. घरेलू खपत को बढ़ावा देना भी सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है. गोयल ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आगामी बैठक में ऐसे उपाय किए जाने की उम्मीद है, जो मांग को तेजी से बढ़ाएंगे और घरेलू विनिर्माण को एक मजबूत बढ़ावा देंगे. उन्होंने इकाइयों से गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया, ताकि भारत उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादों का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बनकर उभरे.

भारत की वैश्विक स्थिति में लगातार मजबूती को रेखांकित करते हुए, गोयल ने विश्वास के साथ कहा कि इस वर्ष का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगा, जो भारतीय उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और जुझारूपन को दर्शाता है. गोयल ने जोर देकर कहा कि कुछ विशेषज्ञ और मीडिया भारत की क्षमता को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं.

गोयल ने कहा कि ये समझौते और इस तरह से समझौतों के लिए कई देशों और समूहों के साथ बातचीत में तेजी, उभरते भारत के साथ व्यापार करने की उनकी इच्छा का परिणाम है. उन्होंने कहा, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उद्योग जगत को कुछ देशों की एकतरफा कार्रवाइयों से उत्पन्न अनावश्यक तनाव या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. उन्होंने उद्यमियों से ऐसे क्षेत्रों की जानकारी देने को कहा, जिन्हें वैकल्पिक बाजारों की आवश्यकता है, क्योंकि मंत्रालय वैश्विक भागीदारों के साथ नए अवसर खोलने के लिए लगातार संपर्क कर रहा है.

भारत के मिलिट्री टेक सेक्टर में जोरदार वृद्धि

दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु बने इनोवेशन हब

2025 में 192.4 मिलियन डॉलर फंडिंग जुटी

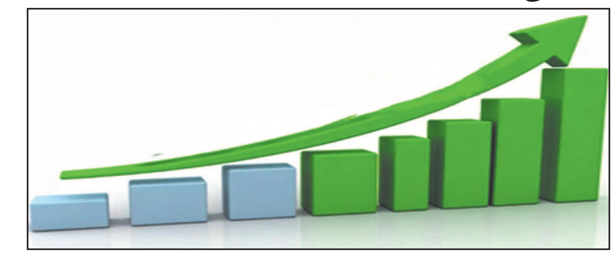

बेंगलुरु, 29 अगस्त. भारत के मिलिट्री टेक सेक्टर में जोरदार वृद्धि देखने को मिल रही है, और इस सेक्टर की वार्षिक फंडिंग पिछले एक दशक में 61 गुना बढ़ी है. यह जानकारी शुक्रवार को जारी हुई रिपोर्ट में दी गई.

मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन द्वारा जारी %इंडिया मिलिट्री टेक रिपोर्ट 2025% के अनुसार, इस सेक्टर के स्टार्टअप्स ने 2025 में अब तक 192.4 मिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो वर्ष की शुरुआत से अब तक इस सेक्टर में आई फंडिंग का सबसे बड़ा आंकड़ा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेक्टर ने 2016 से अब तक 211 फंडिंग राउंड में कुल 611 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. मिलिट्री टेक सेक्टर में फंडिंग डील की संख्या में भी तेज इजाफा हुआ है. जहां 2016 में केवल 3 डील हुई थीं, वहीं 2023 में यह आंकड़ा 36 तक पहुंचा और इस साल अब तक 20 तक पहुंच गया है.

रिपोर्ट पर ट्रैक्सन की सह-संस्थापक नेहा सिंह ने कहा कि भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इनोवेशन, नीति समर्थन और निवेशक भागीदारी से प्रेरित होकर एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है. दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु इस वृद्धि के अग्रणी केंद्र बनकर उभरे हैं, जहां इन क्षेत्रों की कंपनियों ने क्रमशः 194.6 मिलियन डॉलर और 166.1 मिलियन डॉलर जुटाए हैं.

2030 तक देश में होंगे 18,000 सीएनजी स्टेशन

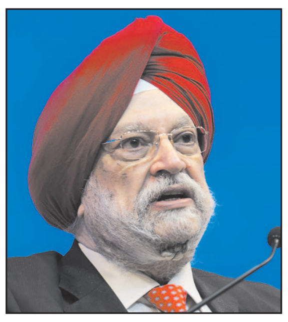

पुरी बोले- 2014 में सिर्फ 738 सीएनजी स्टेशन थे, अब 8,150 से अधिक

पाइपलाइन नेटवर्क 25,429 किमी से बढ़कर 33,475 किमी होगा

नई दिल्ली, 29 अगस्त. केंद्र सरकार की स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देने की पहल के बीच, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या अगले पांच वर्षों में 8,150 से बढ़कर 18,000 से अधिक हो जाएगी.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, पुरी ने सरकार की वन नेशन, वन गैस ग्रिड योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के विजन का खाका बताया. मंत्री ने बताया कि 2014 में देश में केवल 738 सीएनजी स्टेशन थे. आज, यह संख्या बढ़कर 8,150 से अधिक हो गई है, जो बसों, ऑटो और कारों को किफायती, स्वच्छ ईंधन प्रदान कर रहे हैं. 2030 तक, यह नेटवर्क और भी बढ़कर 18,000 से अधिक स्टेशनों तक पहुंच जाएगा.

मंत्री ने कहा कि शहर गैस वितरण नेटवर्क में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है. 2014 में जो केवल 55 भौगोलिक क्षेत्र थे, आज वे बढ़कर 307 हो गए हैं, जो लगभग पूरे देश को कवर करते हैं और 99 प्रतिशत आबादी तथा 96 प्रतिशत भूमि क्षेत्र तक पहुँचते हैं. वर्तमान में, 1.52 करोड़ घर पाइप से प्राकृतिक गैस से जुड़े हैं, जिससे रसोईघर सुरक्षित और स्वच्छ हो गए हैं.

इस बदलाव के पीछे गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, जो पूरे सिस्टम की रीढ़ है. वर्तमान में, पाइपलाइनें 25,429 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, और चल रहे निर्माण के बाद 2030 तक यह 33,475 किलोमीटर तक फैल जाएगी. यह एकीकृत प्रणाली तटों से लेकर दूरदराज के कस्बों तक ईंधन का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करेगी. मंत्री ने यह भी बताया कि देश तेजी से हरित ईंधन की ओर बढ़ रहा है. अब तक 113 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शुरू

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रगति की

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 476 गीगावाट तक पहुँच गई है. इसमें से 240 गीगावाट थर्मल पावर से आती है, जो कुल मिश्रण का 50.52 प्रतिशत है. गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 235.7 गीगावाट है, जो कुल क्षमता का 49 प्रतिशत है, जिसमें 226.9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 8.8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल है. गैस-आधारित बिजली कुल 20 गीगावाट का योगदान देती है. पिछले ग्यारह वर्षों में, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रगति की है.

जियो का आईपीओ 2026 में लॉन्च होगा : अंबानी

मुकेश अंबानी बोले- निवेशकों के लिए बड़ा अवसर

22 करोड़ यूजर्स जुड़े जियो टू 5जी नेटवर्क से

मुंबई, 29 अगस्त. रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 48वीं वार्षिक आम बैठक में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि जियो का आईपीओ अगले साल यानी 2026 की पहली छमाही में आ जाएगा.

मुकेश अंबानी ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि जियो अपने आईपीओ के लिए आवेदन करने की तैयारियाँ कर रहा है. हमारा लक्ष्य 2026 की पहली छमाही तक जियो को सूचीबद्ध करना है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जियो हमारे वैश्विक समकक्षों के समान ही मूल्य सृजित करेगा. मुझे विश्वास है कि यह सभी निवेशकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक अवसर होगा.

रिलायंस जियो ने आज एक और बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 50 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है. मुकेश अंबानी ने जियो को जिंदगी बदलने वाला करार देते हुए शेयरधारकों और ग्राहकों का आभार व्यक्त किया. जियो की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जियो ने कुछ अकल्पनीय काम किए हैं, जैसे वॉयस कॉल मुफ्त करना, डिजिटल भुगतान के तरीकों को बदलना, आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जान फूंकना, और साथ ही दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की रीढ़ का काम करना.

रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने बताया कि देश में 5जी के सबसे तेज रोलआउट के बाद जियो के 5जी ग्राहकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. 22 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स जियो टू 5जी नेटवर्क से जुड़े हैं. उन्होंने यह भी बताया कि जियो जल्द ही अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन शुरू करेगा.

रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने बताया कि देश में 5जी के सबसे तेज रोलआउट के बाद जियो के 5जी ग्राहकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. 22 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स जियो टू 5जी नेटवर्क से जुड़े हैं. उन्होंने यह भी बताया कि जियो जल्द ही अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन शुरू करेगा.

दोपहिया ईवी अपनाने में वित्तीय सहायता देने वाले राज्य आगे

नई दिल्ली, 29 अगस्त. भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, जो राज्य सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, वे दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में अग्रणी हैं.

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सहायक राज्य-स्तरीय नीतियों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में ईवी को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

रिपोर्ट में कहा गया है, अधिकांश राज्य सरकारें हर नए दोपहिया ईवी की खरीद पर सब्सिडी के साथ-साथ कर और पंजीकरण शुल्क छूट जैसे प्रोत्साहन दे रही हैं. वहीं, कुछ राज्यों ने कर और पंजीकरण शुल्क छूट के अलावा कोई अतिरिक्त सब्सिडी नहीं दी.

23 राज्यों के विश्लेषण से गोद लेने के रुझानों में एक स्पष्ट अंतर दिखा. सितंबर 2023 तिमाही में, छह राज्यों, जिन्होंने बिना किसी अतिरिक्त सब्सिडी के केवल कर और पंजीकरण शुल्क में छूट दी थी, में तिमाही-दर-तिमाही आधार पर गोद लेने की दर में 24% की तेज गिरावट दर्ज की गई.

आवासों पर कर राहत जरूरी

नई दिल्ली, 29 अगस्त. राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नरेडको) के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने पिछले कुछ समय से किफायती आवासों की घटती बिक्री पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को करों में छूट देनी चाहिए.

नरेडको के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन से इतर यूनीवार्ता से बात करते हुए हीरानंदानी ने कहा कि पिछली छह तिमाहियों में किफायती आवासों की बिक्री में कमी आई है. इसका कारण यह है कि पिछले कुछ समय में जमीन की कीमत बढ़ी है, निर्माण की लागत बढ़ी है, और सरकारी करों में भी वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा, इन तीनों पर पुनर्विचार की जरूरत है. यह सिर्फ दिल्ली या एक-दो शहरों की बात नहीं है, पूरे देश में जमीन की कीमत बढ़ रही है. हर जगह सर्किल रेट बढ़े हैं. जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, और डेवलपमेंट शुल्क बढ़ाते समय वे यह नहीं सोच रहे हैं कि हमें किफायती आवास को बढ़ावा देने की जरूरत है.

सम्मेलन में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय देश में 94 लाख किफायती आवासों की कमी है, जो साल 2030 तक बढ़कर तीन करोड़ तक पहुंच जाएगी.

रुपया कमजोर, शेयर बाजार में तेजी

मुंबई, 29 अगस्त. विदेशी पूंजी की निकासी और महीने के अंत में अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ने के कारण शुक्रवार को रुपया शुरुआती कारोबार में 18 पैसे गिरकर 87.76 प्रति डॉलर पर आ गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.73 पर खुला और फिर 87.76 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 18 पैसे की गिरावट को दर्शाता है. इससे पहले, बृहस्पतिवार को यह 87.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.99 पर आ गया.

तोखन ने रियल एस्टेट सुधारों पर दिया जोर

केंद्रीय मंत्री ने रेरा को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई

रियल एस्टेट क्षेत्र से बदलावों पर सुझाव आमंत्रित किए गए

नयी दिल्ली, 29 अगस्त. केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने अच्छा काम किया है और अब इसे अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है.

साहू ने नरेडको के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबार करने की आसानी को बढ़ावा देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे कदम निवेशकों में विश्वास बढ़ाएंगे. उन्होंने सभी राज्यों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की सलाह दी. केंद्रीय मंत्री ने रेरा में बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि प्राधिकरण ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अब इसे अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है. उन्होंने इसके लिए रियल एस्टेट क्षेत्र से सुझाव आमंत्रित किए हैं.

आवासन एवं शहरी मामलों के सचिव श्रीनिवास कतकीथला ने कहा कि पिछले दशक में शहरों के विकास पर काफी खर्च किया गया है. उन्होंने रियल एस्टेट कारोबारियों से शहरी क्षेत्र में महज हाउसिंग से आगे देखने और आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान देने का आग्रह किया. नरेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने सरकार से कर प्रणाली को तर्क संगत बनाने की मांग की, जबकि नरेडको के प्रेसिडेंट जी. हरि बाबू ने कहा कि समुचित हाउसिंग के बिना 2047 तक देश को विकसित बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा.

समाचार विशेष

हेमंत की तारीफ कर अमित शाह ने चौंका दिया

सियासी चाल पर सवाल, क्या हैं मायने?

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ की. उन्होंने हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार आरोपों में इस्तीफा देने, कोर्ट से बरी होने और फिर 2024 में विधानसभा उपचुनाव जीतकर दोबारा सीएम बनने की प्रशंसा की.

अमित शाह ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान बताया. उनका यह बयान तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसी प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने महागठबंधन के ही नेता राहुल गांधी और लालू यादव जैसे नेताओं की आलोचना की. खास बात यह कि हाल में ही अमित शाह और हेमंत सोरेन रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक मंच पर दिखे थे.

अमित शाह ने हेमंत सोरेन के इस्तीफा, बरी होने और फिर सीएम बनने की प्रशंसा को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बताया है. अमित शाह का यह बयान उनके पहले के रुख से अलग है, जहां उन्होंने सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. 2024 में साहिबगंज और दुमका रैलियों में शाह ने सोरेन को सबसे भ्रष्ट सरकार का मुखिया बताया था. इस तारीफ के पीछे बीजेपी की छवि को नरम करने और विपक्ष के साथ संवाद की राह खोलने की मंशा दिखती है. अमित शाह का यह बयान बिहार की सियासत को भी प्रभावित कर सकता है जहां बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का सामना महागठबंधन से है. अमित शाह का यह कदम विपक्ष के नेताओं को नरम करने और भविष्य में सियासी समीकरण बदलने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

सियासी मायने और रणनीति को समझिये

जानकार कहते हैं कि अमित शाह का यह बयान सियासी रणनीति का हिस्सा हो सकता है. दरअसल, झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला रहा है, ऐसे में अमित शाह की तारीफ से बीजेपी संभवतः गैर-बीजेपी दलों के साथ तनाव कम करने की कोशिश करने की अर्थ भी सामने आ रहा है. इसके अतिरिक्त यह बिहार और झारखंड में महागठबंधन के साथ भविष्य में गठजोड़ की जमीन तैयार करने का संकेत भी हो सकता है, खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए.

विपक्ष के आरोपों को नरम करने की रणनीति

जानकार कहते हैं कि वर्तमान में जब कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष संसद में भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर बीजेपी को लगातार घेर रहा है, तो ऐसे में शाह की सोरेन की तारीफ से विपक्ष की आक्रामकता को नरम करने की कोशिश दिखती है. ध्यान देने की बात यहां यह भी है कि अमित शाह ने हेमंत सोरेन की लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रिया के सम्मान के लिए तारीफ की. जाहिर है अमित शाह की यह रणनीति विपक्ष की लगातार हमले की धार को कुंद करने और बीजेपी की छवि को नरम दिखाने की रणनीति हो सकती है. जानकार कहते हैं कि अमित शाह का बयान विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर कर सकता है, और संभव है कि यह सोची समझी रणनीति हो.

बृजेंद्र सिंह कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति करेंगे

चंडीगढ़. पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे एवं हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के प्रदेशाध्यक्ष बनने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से मात्र 32 मतों से चुनाव हारे बृजेंद्र सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश मामले विभाग (फोरन अफेयर डिपार्टमेंट) में वाइस चेयरमैन बनाया गया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद कांग्रेस के विदेश मामले विभाग के चेयरमैन होंगे. बृजेंद्र सिंह के साथ डा. आरथी कृष्णा को भी वाइस चेयरमैन बनाया गया है. डा. आरथी कृष्णा कर्नाटक में एनआरआइ फोरम की उपाध्यक्ष हैं. बृजेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के दावेदारों में शामिल थे. कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बृजेंद्र सिंह को जिम्मेदारी मिलने से उनकी प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी पर असर पड़ेगा.

हरियाणा में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. अशोक तंवर के किसी समर्थक को जगह नहीं मिल पाई है. कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है. जातीय समीकरणों के आधार पर बृजेंद्र सिंह की दावेदारी यदि प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त नहीं बैठी तो उन्हें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने की संभावना थी.

सुलझे हुए नेताओं में गिनती

पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की गिनती सुलझे हुए नेताओं में होती है. वह हरियाणा में आइएएस थे और वीआरएस लेकर राजनीति में आए थे. पहली बार हिसार लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने हिसार से उनका लोकसभा का टिकट काट दिया था. लोकसभा के चुनाव में टिकट कटने के बाद कांग्रेस ने जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बृजेंद्र सिंह को चुनाव लड़ने का मौका दिया. तब उनके सामने हरियाणा की भाजपा सरकार में साढ़े चार साल तक साझीदार रहे जेजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे.

विशेष | भाइयों की भिड़ंत से बंगाल की सियासत गरमाई; भाजपा परेशान

मतुआ ठाकुर परिवार में कलह

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मतुआ समुदाय के ठाकुर परिवार में फिर से बवाल मच गया है. केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके बड़े भाई, भाजपा विधायक सुभ्रत ठाकुर के बीच विवाद अब खुले टकराव में बदल चुका है. इस पारिवारिक कलह ने बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

रविवार को ठाकुरनगर स्थित नाट मंदिर, जो मतुआ समुदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है, में शांतनु ठाकुर के समर्थकों ने एक शिविर आयोजित किया. सुभ्रत ठाकुर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नाट मंदिर सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है, राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं. इसके बाद दोनों भाइयों के समर्थकों में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए. शांतनु के गुट ने सुभ्रत पर भक्तों को धमकाने का आरोप लगाया. वहीं सुभ्रत ने पलटवार करते हुए कहा कि शांतनु सामुदायिक संस्थाओं पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं.

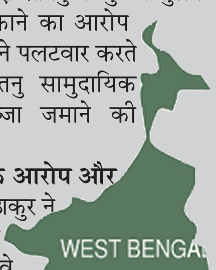

दोनों भाइयों के आरोप और पलटवार- शांतनु ठाकुर ने अपने बड़े भाई पर आरोप लगाया कि वे मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और शायद टीएमसी में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं. वहीं इसके जवाब में सुभ्रत ठाकुर ने कहा, शांतनु समुदाय की शक्ति को हड़पना चाहते हैं. जाति प्रमाण पत्र और मतुआ कार्ड के वितरण में गड़बड़ी हो रही है. असली लाभार्थियों को सीएए का फायदा नहीं मिल रहा. उन्होंने यहां तक कहा कि शांतनु धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं.

परिवार में बंटवारा साफ- सुभ्रत के साथ उनकी मां छबिरानी ठाकुर, बुआ और टीएमसी सांसद ममताबाला ठाकुर, और बहन मधुपर्णा ठाकुर हैं. वहीं शांतनु के साथ उनके पिता मंजुलकृष्ण ठाकुर (पूर्व टीएमसी मंत्री और मतुआ महासंघ के मुख्य सेवायत). उन्होंने दिल्ली से वीडियो जारी कर बेटे शांतनु का समर्थन किया और सुभ्रत की आलोचना की.

युवा वोट पर कांग्रेस की नजर

हैदराबाद. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अलग तरह से राजनीति को परिभाषित करना चाहते हैं. वे कांग्रेस के अंदर सबसे तेजी से उभरते भविष्य के नेता बताए जा रहे हैं. हालांकि उनकी पृष्ठभूमि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है. इस तरह वे आरएसएस के रास्ते कांग्रेस में पहुंचे हैं. उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने की उम्र कम की जानी चाहिए.

हालांकि यह काम उनकी राज्य सरकार नहीं कर सकती है. लेकिन वे इसका क्रेडिट लेने के लिए जोर शोर से इसका ऐलान कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे चुनाव लड़ने की उम्र 25 से घटा कर 21 साल करेंगे. यह काम तभी हो पाएगा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी.

लेकिन ऐसा लग रहा है कि रेवंत रेड्डी ने एक एजेंडा सेट कर दिया है. वे अपेक्षाकृत युवा हैं और युवाओं को कांग्रेस की ओर खींचना चाहते हैं. उनको पता है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में युवाओं का रूझान नरेंद्र मोदी की ओर है. राहुल गांधी उनको आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं. तभी चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल करने का दांव चलने की तैयारी है.